मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना

317. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में शहडोल और सतना में छः सिंचाई योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी और वे कब तक पूरी होंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सतना जिले में दो मध्यम सिंचाई स्कीमें नामश : कुलगढ़ी और भैंसवार निर्माणा-धीन हैं। सीदोल जिले में कोई स्कीम निर्माणाधीन नहीं है ।

(ख) इन स्कीमों की अनुमानित लागत इस प्रकार है ।

कुलगढ़ी	77.34 लाख रुपये
भैंसवार	80.00 लाख रुपये

कुलगढ़ी परियोजना 1971–72 में पूर्ण हो चुकी है और भैंसवार परियोजना के 1973–74 में पूर्ण होने की संभावना है ।

Appointment of Director (Technical) in F.C.I.

318. SHRI R. P. YADAV: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question Nos. 2887 and 2888 on the 14th April, 1972 and state:

(a) whether any Director (Technical) has since been appointed by Government in the Fertilizer Corporation of India; and

(b) if so, since when?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE): (a) and (b). A Director (Technical) was appointed in 1969, but on his subsequent appointment as Managing Director, Fertilizer Corporation of India, the former post remained unfilled for sometime. Presently, there is no post of Director (Technical) in the Corporation.

"Jerking allowance" to Railway Employees

319. SHRI R. P. YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any provision for payment of "jerking allowance" to employees in Indian Railways; and

(b) if so, what categories of employees are entitled to the same?

THE MINISTER OF RAILWAYS SHRI T. A. PAI (a) No such allowance is payable to railway employees.

(b) Does not arise.

भारतीय रेलवे में विभागीय खान-पान व्यवस्था में घाटे के बारे में शिकायतें

320. **श्री हरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में विभागीय खान-पान व्यवस्था घाटे में चल रही है ;

(ख) क्या विभागीय खान-पान एकवों द्वारा बासी तथा मिलावट वाला भोजन सप्लाई करने सम्बन्धी विविध शिकायतें बढ़ती जा रही हैं ; और